प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 21 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 20 – 27 मई 2019 मूल्य पांच रूपए

इस जीत के साथ ही बढ़ी जयराम की चुनौतियां भी

शिमला/शैल। प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा का फिर से कब्जा हो गया है। 2014 में भी चारों सीटें भाजपा के पास ही थी लेकिन इस बार जिस प्रतिशत के साथ यह जीत मिली है उससे देशभर में हिमाचल पहले स्थान पर आ गया है। इस जीत का श्रेय मुख्यमन्त्री ने प्रधानमन्त्री को दिया है। क्योंकि लोगों ने वोट चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम या भाजपा के नाम पर नही बल्कि मोदी के नाम पर दिया है। यह हकीकत है लेकिन इस जीत में मुख्यमन्त्री का अपना भी एक बड़ा योगदान है क्योंकि पूरे चुनाव की कमान प्रदेश में इन्ही के कन्धों पर थी। उन्होने ही प्रदेशभर मे प्रचार की कमान संभाल रखी थी। जो मत प्रतिशत सभी चारों प्रत्याशीयों को मिला है शायद उतने की उम्मीद किसी ने भी नही की थी। इसलिये जीत जितनी बड़ी हो गयी है मुख्यमन्त्री की चुनौतीयां भी उतनी ही बड़ी हो गयी है।

इस चुनाव के बाद अब छः माह के अन्दर प्रदेश को धर्मशाला और पच्छाद में उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। इन उपचुनावों में भी इसी तर्ज पर जीत दर्ज करना मुख्यमन्त्री के लिये व्यक्तिगत चुनौती होगा। अभी इस वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने में सरकार को कर्ज लेने की बाध्यता हो गयी थी और सरकार ने कर्ज लिया भी। लेकिन इन चुनावों के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह ने अपनी चुनावी रैलीयों के संबोधन में विस्तृत आंकड़े रखते हुए यह खुलासा किया है कि मोदी सरकार ने प्रदेश को करीब दो लाख तीस हजार करोड़ दिया है। यह एक बहुत बड़ी रकम है और जब अमितशाह ने यह आंकड़ा दिया है तब इस पर सन्देह करने की कोई गुंजाईश ही नही है। इसलिये प्रदेश की जनता इस पर जवाब चाहेगी कि जयराम के प्रशासन ने इसे कहां खर्च कर दिया जिसके कारण कर्ज लेने की नौबत आ गयी। बल्कि बजट के बाद प्रदेश में सीमेन्ट के दाम बढ़ गये। अब बिजली के रेट दूसरी बार बड़ने की संभावना हो गयी है। प्रदेश के उद्योगों में निवेश बढ़ाने और नया निवेश आमन्त्रित करने के लिये एक निवेशक मीट आयोजित हो चुकी है। इस मीट के बाद कितना निवेश प्रदेश में आ चुका है इसकी कोई जानकारी प्रशासन की ओर से अभी तक सामने नही आयी है जबकि दूसरी मीट के लिये विदेश जाने तक की बात हो रही है। वीरभद्र शासन के दौरान भी इसी प्रशासन ने तीन बार ऐसी निवेश मीट आयोजित की थी करोड़ो रूपया इन पर खर्च किया गया था लेकिन धरातल पर कोई निवेश प्रदेश को मिला नही है। बल्कि प्रदेश द्वारा अपने दम पर चिन्हित की जलविद्युत परियोजनाओं तक में निवेश के लिये कोई आगे नही आया है। जबकि निवेश के रास्ते में आने वाले हर तरह के नियमों का सरलीकरण किया गया है। इस पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए प्रशासन की हर योजना को मुख्यमन्त्री को अपने स्तर पर जांचने की आवश्यकता एक और चुनौती बन जायेगी।

इसी के साथ मन्त्रीमण्डल का विस्तार भी एक और राजनीतिक चुनौती होगा? अनिल शर्मा के त्यागपत्र ओर किश्न कपूर के सांसद बन जाने के बाद मन्त्रीमण्डल में दो स्थान खाली हो गये इन स्थानों पर कौन दो विधायक आयेंगे यह भी एक बड़ा फैसला होगा। हालांकि मुख्यमन्त्री ने यह कह रखा है कि लोस चुनावों में जो ज्यादा बढ़त देगा उसे मन्त्रीमण्डल में स्थान मिलेगा। इस समय हमीरपुर को कोई स्थान मन्त्रीमण्डल में नही मिला है लेकिन स्थान कांगड़ा और मण्डी के खाली हुए हैं। संख्याबल के लिहाज से यह प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं और उस अनुपात से इन्ही जिलों से यह स्थान भरने की मांग आना अनुचित भी नही होगा। इस परिदृश्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह खाली स्थान उपचुनावों के बाद भरे जाते हैं या पहले। बल्कि विभिन्न निगमो/बोर्डो मे ताजपोशीयों के लिये भी कार्यकर्ताओं की ओर से मांग आयेगी और अब इस जीत के बाद यह मांग गलत भी नही होगी। इस तरह इस जीत ने जहां जयराम के नाम एक इतिहास बना दिया है वहीं पर उनकी चुनौतियां भी बढ़ गयी हैं।

क्या कांग्रेस के बड़े नेता ही भाजपा की मदद कर रहे थे पार्टी में उठी चर्चा

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस इस बार फिर सभी चारों सीटों पर भाजपा के हाथों हार गयी है। इस हार का सबसे बड़ा पक्ष यह है कि प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से एक पर कांग्रेस को बढ़त नही मिल पायी है। प्रदेश के छः बार मुख्यमन्त्री रह चुके वीरभद्र सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व केन्द्रिय मन्त्री आनन्द शर्मा और राष्ट्रीय सचिव आशा कुमारी तक कोई भी बड़ा नेता अपने अपने क्षेत्र तक नही बचा सका है। इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा है कि पूर्व अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खु को बहुत पहले ही पद से हटा दिया जाना चाहिये था।

स्मरणीय है कि सुक्खु को इसी वर्ष फरवरी के अन्त में अध्यक्ष पद से हटाया गया था। यह भी तब संभव हुआ था जब आनन्द शर्मा, वीरभद्र सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी ने एक साथ लिखित में सुक्खु को हटाने की मांग रखी थी। जबकि वीरभद्र सिंह 2012 में सरकार बनने के बाद से ही सुक्खु को हटाने की मांग करने लग गये थे। प्रदेश कांग्रेस पर नजर रखने वाले विष्लेशक जानते हैं वीरभद्र सिंह हर उस अध्यक्ष का विरोध करते रहे हैं जो उनकी सहमति से नही बना हो। बल्कि सुक्खु एक मात्र ऐसा अध्यक्ष रहा है जो वीरभद्र सिंह के सीधे विरोध के बाद भी काफी समय तक इस पद पर बना रहा है। कांग्रेस भाजपा और वामदलों जैसा संगठन नही है जहां सरकार और सत्ता से संगठन का कद बड़ा हो जाये। यहां पर प्रायः मुख्यमन्त्री ही संगठन पर

संगठन से अधिक सरकार की नीतियां प्रभावी रहती हैं और शायद इसी कारण से सरकार कभी सत्ता में दोबारा वापसी नही कर पायी है। क्योंकि सरकार बनने के बाद उस संगठन के साथ तालमेल की कमी आ जाती है जो सरकार के निर्देशों के अनुसार न बना हो। प्रदेश में हर बार वीरभद्र संगठन पर हावि रहे हैं और इस हावि होने से संगठन का बजूद नही के बराबर हो जाता रहा है। सुक्खु को हटाने के बाद वह सभी नेता अपने-अपने चुनाव क्षेत्र तक नही बचा सके हैं जिन्होंने सुक्खु को हटाने के लिये लिखित में प्रस्ताव किया था।

सुक्खु को हटाने के बाद जो नयी कार्यकारिणी बनाई गयी थी और उसमें जिस संख्या में पदाधिकारी बनाये गये थे यदि वह लोग भी अपने-अपने बूथ की जिम्मेदारी ले लेते तो भी शायद इतनी शर्मनाक हार न होती। वीरभद्र सिंह छः बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहे हैं इसलिये यह उनकी पहली जिम्मेदारी बनती थी कि वह अपने बाद प्रदेश में नया नेतृत्व तैयार करते किसी को तो अपना उत्तराधिकारी घोषित करते। बल्कि उनकी सारी कार्यप्रणाली से अब अन्त में आकर यही झलक रहा है कि उनके बेटे को बड़ा नेता बनने तक प्रदेश में कांग्रेस खड़ी भी न हो पाये। क्योंकि आज जब सभी नेता अपना-अपना चुनाव क्षेत्र तक नही बचा पाये हैं तो कल यदि इनमें से अधिकांश नेताओं को टिकट से वंचित कर दिया तो यह लोग उसका विरोध कैसे कर पायेंगे। क्योंकि कोई भी नेता वीरभद्र के साये से बाहर निकलकर अपना अलग से बजूद नही बना पाया है।

इसी चुनाव में कांग्रेस नेता पूर्व मन्त्री विजय सिंह मनकोटिया ने वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि अपने केसों से बचने के लिये उन्होने पार्टी को भाजपा के आगे एक तरह से गिरवी रख दिया है। मनकोटिया के इस आरोप पर यदि गंभीरता से नजर दौड़ाई जाये तो मण्डी से होने वाले किसी भी

शेष पृष्ठ 8 पर.....

सरकार के प्राकृतिक खेती अपनाने के कदम को नीति आयोग ने सराहा: राज्यपाल

शिमला/शैल। प्रदेश को जहरमुक्त करने और किसानों की आय को दोगुणा करने के लिए शुरू की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से जुड़ने वाले बेहतरीन किसानों के लिए बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में

एक दिवसीय अधिकारी एवं उत्तम किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती अपना चुके 321 किसानों और 200 के करीब अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के समापन अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को इस खेती विधि को सच्चाई के साथ अपनाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा प्रदेश में इस खेती विधि की सफलता को देखकर नीति आयोग ने भी सराहना की है। उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह नीति आयोग के उपाध्यक्ष से उनकी भेंट हुई है और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है।

राज्यपाल ने रसायनिक खेती का असर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम सबके सामने हैं। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में प्राकृतिक खेती समय की मांग बनकर उभरी है। राज्यपाल ने कहा कि जो किसान इस खेती विधि से पैदावार कर रहें हैं उनके उत्पादों को बाजार तक उपलब्ध करवाने के लिए लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब पूरा प्रदेश प्राकृतिक खेती को अपना लेंगे तो बाहरी राज्यों में हिमाचल को जहरमुक्त राज्य के तौर पर पहचाना जाएगा और इससे किसानों को उनके उत्पादों के सही दाम मिलेंगे। कार्यशाला के दौरान राज्यपाल ने किसानों के साथ सीधा संवाद भी किया।

कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने बताया कि इस वर्ष इस सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि से 50 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी जिलों को लक्ष्य दिए गए हैं और इन पर काम होना शुरू हो गया है।

इस मौके पर प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा ने कहा कि किसानों और अधिकारियों की ओर से जो सुझाव आए हैं उन पर गौर किया जाएगा और उन्हें ध्यान में रखते हुए भविष्य की कार्य योजना तैयार की जाएगी। कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया।

कार्यशाला में कृषि निदेशक देशराज शर्मा ने कहा कि किसानों को विभाग की ओर से जो भी सुविधाएं चाहिए वो मुहैया करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वाइस चांसलर डॉ एचसी शर्मा, जिला उपायुक्त सोलन विनोद कुमार, एसपी सोलन मधुसूदन और सभी जिलों के कृषि विभाग के पीडी, डीपीडी, एसएमएस, एटीएम और बीटीएम और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

राज्यपाल ने की पूर्व प्रधान मंत्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सद्भावना चौक छोटा शिमला

में पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि एवं शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र के लोग उनके साथ उपस्थित थे।

राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित लोगों को सद्भावना शपथ भी दिलाई।

इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति गीत तथा भजन प्रस्तुत किए।

राज्यपाल के सलाहकार डॉ. शशिकांत शर्मा और नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय भी अन्यों के सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि मानव और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान ही

नहीं, बल्कि उनका समग्र विकास होना चाहिए। उन्होंने बच्चों में संस्कार की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो।

राज्यपाल कुरुक्षेत्र के सुजरा –बाबैन में संजय गांधी ओम प्रकाश गर्ग मैमोरियल पब्लिक स्कूल के नये भवन के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य बच्चों को सुशिक्षित बनाना है, जिनमें विज्ञान और तकनीकी की पूर्ण जानकारी हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और वे संस्कारित बनें। जिस शिक्षा में यह उद्देश्य नहीं है वह अधूरी है और इसके बिना हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। यह कोई व्यापार नहीं है बल्कि मानव और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षण का उनका 35 वर्षो का लम्बा अनुभव रहा है और एक विद्यार्थी का कैसे समग्र विकास संभव है, इसका उन्हें अनुभव है।

राज्यपाल ने कहा कि अक्षर ज्ञान की कमी नहीं है बल्कि कमी है तो संस्कारों की। उन्होंने समाज में फैले नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बुराई हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बच्चों में संस्कार की कमी दिखाई देती है और ऐसी शिक्षा किस काम की है।

उन्होंने गुरु–शिष्य परम्परा को बढ़ावा देते हुए जीवन मूल्यों को बनाये रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि माता–पिता और शिक्षकों की अधिक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों में संस्कार की शिक्षा दें। उन्होंने स्कूल प्रबंधान समिति को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

राज्यपाल ने इससे पूर्व, स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया।

इससे पूर्व, राज्यसभा सांसद ले. जनरल डॉ. डी.पी. वत्स ने शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य देवव्रत के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की।

इससे पूर्व, संजय गांधी ओम प्रकाश गर्ग मैमोरियल पब्लिक स्कूल की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष पवन गर्ग ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा स्कूल गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का जन्म भारत की धरती पर हुआ:आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आध्यात्मवाद संस्कृति की देन है, जिस पर आज अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ व्यापक स्तर पर मिल सके।

राज्यपाल कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट सेंटर में अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेष (स्नातकोत्तर) संगठन के हरियाणा चौप्टर द्वारा ''मस्क्युस्कैलेटल डिस्ऑर्डर'' पर 4वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अधयक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस सम्मेलन में करीब 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विभिन्न संस्थानों के स्नातकोत्तर शाधार्थियों ने 185 शोधपत्र प्रस्तुत किए।

उन्होंने कहा कि भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले मानव के स्वास्थ्य के दृष्टिगत चिकित्सा पद्धति की रचना की, जो जीवन शैली का एक हिस्सा थी। जीवन का मूल उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम को करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना है, जिसका पहला आधार ही स्वस्थ शरीर का होना है। अस्वस्थ व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी समाज में योगदान नहीं कर पाता है। स्वस्थ शरीर ही सकारात्मक सोच से विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेष (स्नातकोत्तर) संगठन इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि आयुर्वेद का जन्म भारत की धरती पर हुआ और यह विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। लेकिन, एलोपैथी की तरह इस पर व्यापक अनुसंधान नहीं हुआ। संपूर्ण मानव को जो लाभ इस चिकित्सा पद्धति से मिलना था, वह उससे वंचित रह गया। उन्होंने युवा चिकित्सकों से इस पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि, जिन ऋषि–मुनियों ने इस चिकित्सा पद्धति को दिया उनका शोध आध्यात्मवाद पर टिका था और वह इतना स्टीक था कि जो गुण किसी औषधि में मिलते थे वह आज भी प्रयोगशाला में उतने ही गुणों के साथ उपलब्ध है।

राज्यपाल ने कहा कि यह जीवनदायिनी चिकित्सा पद्धति पंचतत्वों को आधार बनाकर प्रकृति से बनी है, जिसके कोई साईड इफैक्ट्स नहीं है। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार पर बल दिया।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे चिकित्सकों को भी सम्मानित किया। उन्होंने संगठन की स्मारिका का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम निदेशक डॉ. बलबीर सिंह संधू तथा आयोजन सचिव डॉ. राजा सिंघला ने राज्यपाल का स्वागत किया।

आर्य समाज मंडी के प्रधान बने हरीश चंद्र बैहल

शिमला/शैल। आर्य समाज मंडी के वार्षिक चुनाव में हरिश चद्र बैहल को प्रधान चुना गया। आर्य समाज मंदिर में यह चुनाव रोशनलाल बैहल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकारिणी व अंतरंग सभा का भी गठन हुआ। जिसमें संरक्षक के तौर पर रोशनलाल बैहल, रतनलाल वैद्य, किशोरी लाल गोयल, देवेंद्र नाथ वैद्य चुने गए। कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपप्रधान सुरेश टंडन, उपप्रधान डॉ देवव्रत वैद्य, कार्यकारी प्रधान अमृतलाल बैहल, मंत्री गजेंद्र कपूर, उप मंत्री देवराज आर्य, कोषाध्यक्ष खेम सिंह सेन, वेद प्रचार अधिष्ठाता वेद मित्र शर्मा, तकनीकी कार्य प्रभारी प्रियव्रत वैद्य, मीडिया प्रभारी योगेश कुमार, लेखा परीक्षक जगदीश वैद्य , पुस्तकालय प्रभारी अजय शर्मा को चुना गया। इसके अलावा 13 सदस्यीय अंतरंग सभा के सदस्य भी चुने गए जिसमें सरला बैहल, दयावती बैहल विद्यावती वैद्य, अनीता लोहिया, वेद कुमारी वैद्य, मृदुला वैद्य, अरुणा कौशिक, भूपेंद्र पाल मल्होत्रा, वेद प्रकाश वैद्य, दीनानाथ वैद्य, अशोक भारती, भूपेंद्र कुमार लोहिया व यशपाल गोयल शामिल है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

लम्बे समय तक इतिहास का हिस्सा बन कर रहेंगे लोकसभा चुनाव:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव लम्बे समय तक इतिहास का हिस्सा बन कर रहेंगे। लोकसभा का यह सबसे लम्बा चुनाव जिसमें सबसे अधिक मत भाजपा ने हासिल किया चुनाव में लोगो ने भाजपा को समर्थन दिया सभी बधाई के पात्र हैं। हिमाचल में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त हालिस हुई। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में 69% वोट शेयर लेकर पहले स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 30 हजार से ज्यादा की बढ़त 34 विधानसभा क्षेत्रों मे 20 हजार से ज्यादा 21 विधानसभा क्षेत्रों में 10 हजार ज्यादा चार विधानसभा क्षेत्र है जहां 10 हजार या उससे कम की बढ़त भाजपा को

मिली है। पूरे प्रदेश में भाजपा को 68. 41 वोट हालिस हुए जबकि कांग्रेस को 27% वोट हासिल हुए। सभी लोकसभा सीटों पर तीन लाख से अधिक के अन्तर से जीत हालिस हुई है। कांगड़ा की लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा बढ़त भाजपा को मिली है जबकि मण्डी दूसरे, हमीरपुर तीसरे और शिमला चौथे स्थान पर रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बढ़त नहीं ले पाए हैं। कहा कि जहा कांग्रेस के गढ़ होते थे वहां भी भाजपा ने इस चुनाव में अपनी बढ़त बनाई है। जिसमें रोहडू, रामपुर, अर्की और हरोली विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मण्डी सदर से भाजपा को 27491 की बढ़त कांगड़ा में पवन काजल के विधानसभा क्षेत्र से 23643 की बढ़त भाजपा को, धनी राम शांडिल के विधानसभा क्षेत्र 16,188 मतों की बढ़त और हमीरपुर के नैनादेवी से 10,833 मतो की बढ़त भाजपा को मिली है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अपने गढ़ अर्की से 29,000, मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र 14,921 की बढ़त मिली है। प्रदेश में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 39,970 मतों की बढ़त मिली है जबकि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज से 37,147 की बढ़त और दूसरे स्थान पर जोगिन्द्र नगर 36,292 की बढ़त लेकर तीसरे स्थान पर रहा। आज तक के इतिहास में हिमाचल से अपने विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में किसी भी मुख्यमन्त्री ने इतनी बढ़त नही दिलाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। देश के अनुरूप माहौल हिमाचल में भी रहा। चुनाव का सारा श्रय मोदी और शाह को जाता है। भाजपा ने 2019 की शुरूआत 2014 का चुनाव जीतने के बाद ही कर दी थी। जीत के मोदी बधाई के पात्र हैं। कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर यह मेरे लिये नया काम था। पार्टी और जनता का पूरा सहयोग मिला। जय राम ने कहा कि चुनाव के दौरान कुल 106 जन सभा की हैं। चुनाव में प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। इस जीत की कल्पना कांग्रेस ने भी नहीं की थी। जय राम ठाकुर ने कहा कि मैंने 15 महीने के कार्यक्रम में मैंने बोला कम और सुना है। प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते थे कि हम जो कहेंगे वही होगा। इस चुनाव में यह भरम टूटा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनादेश है इसका सम्मान करना चाहिए। इस व्यापक जनादेश के लिए मोदी को बधाई देता हूँ। देश अब कांग्रेस मुक्त हो गया है। इस जनादेश का अभिनंदन करता हूँ। वीरवार को आए लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा ने प्रदेश की सभी चारों सीटें जीती।

प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के लिए बड़े फैसले लेगी सरकार:कृषि मंत्री

सोलन/शैल। कृषि, जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्राकृतिक खेती में सही तकनीक के उपयोग से भूमि वातावरण से ही फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है तथा शून्य लागत प्राकृतिक तकनीक में कृत्रिम उत्पादों का प्रयोग होने के कारण वातावरण पर भी इस का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। डॉ. मारकंडा डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में एक दिवसीय अधिकारी एवं उत्तम किसान कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला में प्रदेश भर में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती अपना चुके 321 किसानों और 200 के करीब अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में प्रदेश को जहरमुक्त करने का आंदोलन बल पकड़ रहा है यह अपने आप में सराहनीय है।

कृषि मंत्री ने कहा कि पर्यावरण और इस खेती से उगने वाला अनाज रसायनमुक्त होता है। इस कृषि पद्धति में देसी गाय, पारंपरिक देसी बीजों का संरक्षण पर बल दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती अपना चुके किसानों के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को देसी नस्ल की गाय मुहैया करवाने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है और जून माह में किसानों को गाय मुहैया करवाना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस खेती विधि के बारे में नौणी और पालमपुर विश्वविद्यालयों में शोध का कार्य किया जाएगा।

कार्यशाला में प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक राकेश कंवर, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल, कृषि निदेशक देशराज शर्मा, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वाइस चांसलर डॉ एचसी शर्मा, जिला उपायुक्त सोलन विनोद कुमार, एसपी सोलन मधुसूदन और सभी जिलों के कृषि विभाग के पीडी, डीपीडी, एसएमएस, एटीएम और बीटीएम और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

प्रधानमन्त्री मोदी पर किया देश की जनता ने विश्वास:अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ

शिमला/शैल। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को मिले एतिहासिक जनादेश का स्वागत करते हुए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि मोदी सरकार की जनकल्याण नीतियों और पारदर्शी सुशासन पर देश के जागरूक मतदाता ने अपनी मोहर लगाकर सबसे बड़े लोकतन्त्र का पूरे विश्व में मान बढ़ाया है। प्रधानमन्त्री मोदी की कथनी और करनी पर देश की जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें फिर परचंड बहुमत के साथ देश की बागडोर सौंपी है। महासंघ के अध्यक्ष एवं संयोजक विनोद कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के चार सांसदों को रिकॉर्ड तौड़ मर्जिन से जीताकर जनता ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और उनकी सफल नीतियों और कार्यक्रमों में अपना विश्वास व्यक्त किया है जिसके लिए मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और उनका पूरा मन्त्रिमण्डल भी बधाई का पात्र है। महासंघ के नेताओं विनोद कुमार, रविन्द्र मैहता, गोबिन्द बरागटा, हरि सिंह, शीला चन्देल, अजय जोशी, राकेश शर्मा, रूपलाल ठाकुर, सुमन वनियाल, विवेक गुलेरी, राकेश चन्देल, मनोज कुमार इत्यादि ने जारी प्रैस ब्यान में कहा है कि प्रधानमन्त्री मोदी की सरकार ने पिछले 5 वर्ष सरकारी तन्त्र में शून्य भ्रष्टाचार नीति पर अपनी प्रतिबद्धता को सफल बनाया, जिसका यह सबूत है कि केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल के किसी भी मन्त्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मोदी मन्त्रिमण्डल के किसी भी मन्त्री को देश की जनता ने इन चुनावों में हारने नहीं दिया, जो इस देश के इतिहास में एक बड़ी घटना है।

राज्य वन सेवा प्रशिक्षुओं का उत्तर भारत का दौरा

शिमला/शैल। राज्य वन सेवा प्रशिक्षण कालेज (एस. एफ.एस.), देहरादून से हिमालयी वनस्पति, वन व वन्यप्राणी प्रबन्धन के अध्ययन हेतु,

लगभग 40 प्रशिक्षुओं का दल, हिमाचल में शिमला, मनाली, सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में, वन प्रबन्धन की बारीकियों का प्रशिक्षण लेने के लिए शिमला पहुँचा। कुनाल सत्यार्थी प्रिन्सीपल (सैन्ट्रल अकैडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसीज) व सरिता कुमारी (कोर्स डारेक्टर) की अगुवाई में यह प्रशिक्षु, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब व जम्मू कश्मीर राज्यों के वनों का अध्ययन कर रहे हैं। एस.एफ.एस, देहरादून में वर्ष 2018 – 20 बैच में चार राज्यों ओड़ीसा, कर्नाटका, छतीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के प्रशिक्षु प्रशिक्षणरत हैं।

टालैण्ड शिमला स्थित वन मुख्यालय में इन प्रशिक्षओं को सम्बोधित करते हुए, अजय कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) हिमाचल प्रदेश (डॉ सविता, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी), अजय श्रीवास्तवा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी), अनु नागर मुख्य अरण्यपाल (एच0 आर0 डी0) ने हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र व वनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अनु नागर ने वन विभाग हिमाचल के अवलोकन के साथ – साथ वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों से प्रशिक्षुओं को अवगत करवाया। डॉ सविता, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) – कम – मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक ने हिमाचल प्रदेश वन्य प्राणी प्रभाग व प्रदेश के वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज, वन विभाग को वन्य प्रणियों के संरक्षण के साथ – साथ वन्य जीव – मानव संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश में चल रही बन्दरों की समस्या व बन्दर – नसबन्दी कार्यक्रम की जानकारी भी प्रशिक्षुओं से साझा की। अजय कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) हिमाचल प्रदेश ने प्रशिक्षुओं को जैव – विविधता, वनों की सुरक्षा, व वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाते हुए आह्वान किया कि उन्हें अपने – अपने क्षेत्रों की पहचान कर किसी एक विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी तथा प्रशिक्षु अपने कार्य क्षेत्र में सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें ताकि वन प्रबन्धन में हो रहे निरन्तर बदलावों की आपूर्ति की जा सके।

इस अवसर पर विजय लक्ष्मी तिवारी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एम. एण्ड ई.) राकेश सूद अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एडमिन), के.एस. ठाकुर अतिरिक्त प्रधाान मुख्य अरण्यपाल(कैम्पा), आर.के.गुप्ता, मुख्य अरण्यपाल शिमला, नागेश गुलेरिया, मुख्य अरण्यपाल, (एम. एण्ड ई.) भी उपस्थित थे व उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभ कामनाएं दी।

बड़ोग बाईपास पर 6 दिन के लिए वाहनों की आवाजाही बंद

शिमला/शैल। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बड़ोग बाईपास (कुमारहटी से दोहरी दीवार, सोलन तक) वाहनों की आवाजाही के लिए 25 मई 2019 से 30 मई 2019 तक 6 दिन के लिए बंद रहेगा।

यह आदेश बड़ोग बाईपास पर कुमारहटी जंक्शन से सोलन शहर की तरफ 40 मीटर आगे बनाए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।

यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए उपयोग होने वाले वाहनों तथा रबौन, आंजी, शमलेच, तपन हुंडाई, चिलां कलान इत्यादि गांवों के निवासियों के लाईट मोटर व्हीकल पर लागू नहीं होंगे।

उन्होंने पुलिस विभाग को इस संबंध में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है।.....चाणक्य

सम्पादकीय

बड़ी जीत-बड़ी परीक्षा

जनादेश 2019 में देश की जनता ने देश के भविष्य की बागडोर एक बार फिर से मोदी के हाथों में सौंपी है। भाजपा को 2014 से भी ज्यादा जन समर्थन इस बार मिला है। यह जीत भाजपा से अधिक मोदी के जनमत संग्रह के रूप में आयी है। इस नाते यह जीत जितनी बड़ी है यह उतनी ही बड़ी परीक्षा भी साबित होगी यह प्रकृति का नियम है। जनता ने जो विश्वास मोदी में व्यक्त किया है उस विश्वास पर मोदी कितने खरे उतरते हैं उसका पता हर आने वाले दिन से लगता जायेगा। जितना बड़ा जनादेश मोदी को मिला है उसके साये में किसी भी योजना और किसी भी फैसले को अमली जामा पहनाने में मोदी को संसद में किसी भी अवरोध का सामना नही करना पड़ेगा यह स्पष्ट है। अवरोध तो 2014 में भी कोई ज्यादा नही थे लेकिन उस समय किये गये वायदे उतने पूरे नही हुए हैं जितने किये गये थे।

ऐसा बहुत कम होता है कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में जीत के जिस आंकड़े का अनुमान लगाया गया हो वही आंकड़ा एग्जिट पाल में भी आये और फिर परिणाम आने पर हकीकत में भी बदल जाये। इस बार ऐसा ही सामने आया है। संभव है कि जो लोग या दल चुनाव हार गये हैं वह अपनी हार के लिये एक बार फिर ई वी एम मशीनों को दोष दें। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठायें। चुनाव आयुक्तों में जिस तरह से मतभेद होने का तथ्य सामने आया है उससे निष्पक्षता पर सवाल उठने स्वभाविक हैं। विपक्ष लम्बे समय से चुनाव आयोग से ई वी एम और वी वी पैट को लेकर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष की मांग को आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी ने ठुकरा दिया है। लेकिन इससे जनता में सन्देह भी बना है और यही सन्देह आने वाल समय में जनाक्रोश का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं उनमें सबसे पहले चुनाव आयोग पर ही प्रश्न उठेंगे क्योंकि उसके लिये आधार और इस आधार को चुनाव परिणामों के बाद आये कुछ विडियोज़ पुख्ता भी करते हैं।

लोकतन्त्र जनता के भरोसे से चलता है और यह जनता ही है जो भरोसा टूटने पर सत्ता से बेदखल भी कर देती है। 1971 से लेकर 1980 तक के काल खण्ड में जो कुछ घटा है आज उसकी पुर्नरावृति की आशंकाएं उभरने लगी हैं। 1971 के बड़े जनादेश के बाद 1975 में देश ने आपातकाल देखा। आपातकाल के बाद सत्ता बदली लेकिन अढ़ाई कोस चलकर ही दम तोड़ा गयी थी। आपातकाल का कारण भी संवैधानिक संस्थानों पर से विश्वास का टूटना बना था। आज भी संस्थान भरोसा खोने लग गये हैं। इसलिये इस भरोसे को पुन: स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिये और यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमन्त्री की बनती है। इसलिये अब जब परिणाम आ गये हैं और सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है तब सरकार को चुनाव आयोग पर उठने वाले सवालों का निराकरण करने के लिये पहल करनी होगी। चुनाव आयोग से मांग है कि ई वी एम के स्थान पर पुन: बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जायें। इस पर जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वी वी पैट आवश्यक कर दिया गया है तब यह मांग यहीं पूरी हो जाती है। इसके बाद कम से कम 50% वी वी पैट की पर्चीयों का मिलान और उसकी गिनती ई वी एम से पहले करने की मांग है। सर्वोच्च न्यायालय ने 50% की मांग को इसलिये ठुकरा दिया था कि इसमें समय ज्यादा लगेगा और चुनाव परिणाम आने में देर लगेगी। इसलिये सर्वोच्च न्यायालय ने इसे केवल पांच वी वी पैट की गिनती तक सीमित कर दिया। चुनाव आयोग ने नियमों का हवाला देकर इस गिनती को मशीन की गिनती से पहले करवाने से भी इन्कार कर दिया।

इस परिदृश्य में सबसे पहले यह सवाल उठता है कि क्या जन विश्वास को पूरे तार्किक आधार पर बहाल करना प्राथमिकता होनी चाहिये या नही। इस विश्वास को बहाल करने के लिये यदि शतप्रतिशत वी वी पैट और ई वी एम मशीन के मिलान को अनिवार्य कर दिया जाये तो इसमें दो दिन का समय यदि ज्यादा भी लग जाये तो इसमें क्या फर्क पड़ जायेगा। इसके लिये पूरी चुनाव प्रक्रिया को सात चरणों तक लम्बा खीचनें की बजाये तीन से चार चरणों में ही पूरा किया जा सकता है। आज जिस ढंग से चुनाव आयोग अविश्वास का केन्द्र बन चुका है वह लोकतन्त्र के लिये किसी भी विदेशी आक्रमण से ज्यादा घातक होगा। इस समय चुनाव प्रक्रिया में तुरन्त प्रभाव से संशोधन करने की आवश्यकता है। लोकतन्त्र में चुनावों का इस कद्र मंहगा होना लोक और तन्त्र को दो अलग-अलग ईकाईयां बना रहा है। चुनाव सुधारों की एकदम प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता है और इसके लिये सरकार को तुरन्त पहल करनी होगी। इसके लिये आज विपक्ष को भी इन सुधारों की ही मांग प्राथमिकता पर करनी होगी।

ना मुद्दे ना उम्मीदवार सिर्फ मोदी सरकार

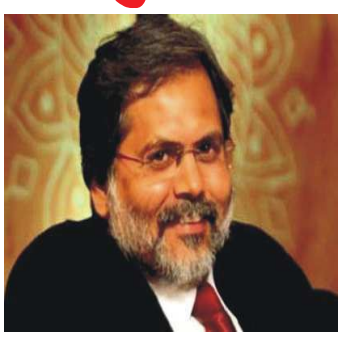

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

गुलाब की पंखुडियों से पटी पडी जमीन। गेंदा के फूलो से दीवार पर लिखा हुआ धन्यवाद । दरवाजे से लेकर छत तक लड्डु बांटते हाथ। सडक पर एसयूवी गाडियों की कतार। और पहली बार पांचवी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी खुला हुआ । ये नजारा कल दिल्ली के नये बीजेपी हेडक्वाटर का था । दीनदयाल मार्ग पर बने इस पांच सितारा हडक्वाटर को लेकर कई बार चर्चा यही रही कि दीनदयाल के आखरी व्यक्ति तक पहुंचने की सोच के उलट आखरी व्यक्ति तो दूर बीजेपी कार्यकत्ताओं के लिये हेडक्वाटर एक ऐसा किला है जिसमें कोई आसानी से दस्तक दे नही सकता। जबकि अशोक रोड के बीजेपी हेडक्वाटर में तो हर किसी की पहुंच हमेशा से होती रही । और 2014 की जीत का नजारा कैसे 2019 में कही ज्यादा बडी जीत के जश्न के साथ अशोका रोड से दीनदयाल मार्ग में इस तरह तब्दिल हो जायेगा कि बीजेपी को समाज का पहला और आखरी व्यक्ति एक साथ वोट देगें। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था और ऐसा हो सकता है ये कभी किसी ने सोचा ना होगा कि बहुमत की सरकार दूसरी बार अपने बूते करीब 50 फिसदी वोट के साथ सत्ता में बरकरार रहे। और सिर्फ चार राज्य छोड कर (तमिलनाडु , आधप्रदेश, केरल और पंजाब) हर जगह बीजेपी ऐसी घमक के साथ सत्ता की डर अपने साथ रखेगी कि ना सिर्फ क्षत्रप बल्कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को भी अपनी राजनीति को बदलने या फिर नये सिरे से सोचने की जरुरत पडेगी। जबकि देश के सामने सारे मुद्दे बरकरार है। बेरोजगारी, किसान, मजदूर, उत्पादन कुछ इस तरह गहराया हुआ कि आर्थिक हालात बिगडे हुये है। उस पर घृणा, पाकिस्तान से युद्द, हिन्दु राष्ट्र की सोच और गोडसे को जिन्दा भी किया गया लेकिन फिर भी जनादेश के सामने मुद्दे-उम्मीदवार मायने रखे ही नही। जातिया टूटती नजर आयी। उम्मीद और आस हिन्दुत्व का जोगा उडकर देशभक्ति व राष्ट्रवाद में इस तरह खोया कि ना सिर्फ पारंपरिक राजनीतक सोच बल्कि अतीत की समूची राजनीतिक थ्योरी ही काफूर हो गई । पश्चिम बंगाल में धर्म को अफिम कहने मानने वाले वामपंथी वोटर खिसक कर धर्म का जाप करने वाली बीजेपी के साथ आ खडे हुये। और जिस तरह 22 फीसदी वामपंथी वोट एकमुश्त बीजेपी के साथ जुडे गया उसने तीन संदेश साफ दे दिये। पहला, वामपंथी जमीन पर जब वर्ग संघर्ष के नारे तले काली पूजा मनायी जाती है तो फिर वही काली पूजा, दशहर और राम की पूजा तले धर्मिक होकर मानने में क्या मुश्किल है। दूसरा, वाम जमीन पर सत्ता विरोध का स्वर हमेशा रहा है तो वाम के तेवर- संगठन-पावर खत्म हुआ तो फिर विरोध के लिये बीजेपी के साथ ममता विरोध में जाने से कोई परेशानी है नहीं। तीसरा, मुस्लिम के साथ किसी जाति का कोई साथ ना हो तो फिर मुस्लिम तुष्टिकरण या मुस्लिम के हक के सवाल भी मुस्लिमों के एक मुश्त वोट के साथ सत्ता दिला नहीं सकते या फिर सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में आ सकते है ।

दरअसल , जनादेश तले कुछ सच उभर कर आ गये और कुछ सच छुप भी गये। क्योंकि 2019 का जनादेश इतना स्थूल नहीं है कि उसे सिर्फ मोदी सत्ता की एतिहासिक जीत कर खामोशी बरती जा जाये। क्योकि बंगाल से सटे बिहार में एमवाय जोड टूट गया। लालू यादव की गैर मौजूदगी में लालू परिवार के भीतर का झगड़े और महागंठबंधन के तौर तरीके ने उस मिथ को तोड दिया जिसमें यादव सिर्फ आरजेडी से बंधा हुआ है और मुसलिमों को ठौर महागंठबंधन में ही मिलेगी ये मान लिया गया था। चूकि तेजस्वी, राहुल, मांझी, कुशवाहा, साहनी के एक साथ होने के बावजूद अगर महागंठबंधन की हथेली खाली रह गयी तो ये सिर्फ नीतिश-मोदी-पासवान की जीत भर नहीं है बल्कि सामाजिक समीकरण के बदलने के संकेत भी है। और जिस तरह बिहार से सटे यूपी में अखिलेश-मायावती के साथ आने के बावजूद यादव-जाटव तक के वोट ट्रासफर नहीं हुये उसमें भविष्य के संकेत तो दे ही दिये कि अखिलेश यादव ओबीसी के नेता हो नहीं सकते और मायावती का सामाजिक विस्तार अब सिर्फ जाटव भर है और उसमें भी बिखराव हो रहा है । फिर बीजेपी ने जिस तरह हिन्दु राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर वोट का ध्रुवीकरण किया उसने भी संकेत उभार दिये कि कांग्रेस जिस तरह सपा-बसपा से अलग होकर उंची जातियों के वोट बैंक को बीजेपी से छिन कर अपने अनुकुल करने की सोच रही थी जिससे 2022 (यूपी विधानसभा चुनाव) तक उसके लिये जमीन तैयार हो जाये और संगठन खडा हो जाये उसे भारी धक्का लगा है।

जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस के लिये भी बड़ा संदेश इस जनादेश में छुपा है। एक तरफ बीजेपी का संकट ये हो कि अब वह संगठन वाली पार्टी कम कद्दावर नेता की पहचान के साथ चलने वाली सफल पार्टी के तौर पर ज्यादा है। यानी यहां पर बीजेपी कार्यकर्त्ता और संघ के स्वंयसेवक की भूमिका भी मोदी के सामने लुप्त सी हो गई । जो कि वाजपेयी-आडवाणी युग से आगे और बहुत ज्यादा बदली हुई सी पार्टी है । क्योंकि वाजपेयी काल तक नैतिकता का महत्व था । मौरल राजनीति के मायने थे । तभी तो मोदी को भी राजधर्म बताया गया और भ्रष्ट यदुरप्पा को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन मोदी काल में महत्वपूर्ण सिर्फ जीत है । इसलिये महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे भी देशभक्त है और सबसे ज्यादा कालाधन खर्च कर चुनाव जीतने का शाह मंत्र भी मंजूर है। पर इसके सामानांतर कांग्रेस के लिये संभवत ये सबसे मुश्किल दौर है। क्योंकि बीजेपी तो मोदी सरीखे लारजर दैन लाइफ वाले नेता को साथ लेकर भी पार्टी के तौर पर लडती दिखायी दी। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी होकर भी सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी को ही देखकर मंद मंद खुश होती रही। लड़ सिर्फ राहुल रहे थे। प्रियंका गांधी का जादुई स्पर्श अच्छा लग रहा था। लेकिन कांग्रेस कही थी ही नही। और शायद 2019 के जनादेश में जिस तरह की सफलता जगन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में मिली उसने कांग्रेस की सबसे बडी कमजोरी को भी उभार दिया कि उसने ना तो अपनो को सहेजना आता है ना ही कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के तौर पर संभालना आता है। क्योंकि एक वक्त ममता भी कांग्रेस से निकली और जगन रेड्डी भी कांग्रेस से निकले। दोनों वक्त गांधी परिवार में सिमटी कांग्रेस ने दिल बडा नहीं किया उल्टे अपने ही पुराने नेताओं के सामने कांग्रेस के एतिहासिक सफर के अंहकार में खुद को डुबो लिया। और जिस मोड पर राहुल गांधी ने कांग्रेस संभाली तो वह पार्टी को कम नेताओं को ही ज्यादा तरजीह दे मान बैठे कि नेताओं से कांग्रेस चलेगी। असर इसी का है कि कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नेता को इतना पावर नहीं कि वह बाकियो को हांक सके। तो मध्यप्रदेश में कमलनाथ के सामानातंर दिग्विजय हो या सिंधिया या फिर राजस्थान में गहलोत हो या पायलट या फिर छत्तिसगढ़ में भूपेश बघेला हो या ताम्रध्वज साहू व टीएस सिंह देव। सभी अपने अपने तरीके से अपने ही राज्य में काग्रेस को हाकते रहे। तो कार्यकर्त्ता भी इसे ही देखता रहा कि कौन सा नेता कितना पावरफुल है और किसके साथ खडा हुआ जा सकता है या फिर अपनी अपनी कोटरी में सिमटे कांग्रेसी नेताओं को संघर्ष की जरुरत क्या है ये सवाल ना तो किसी ने जानना चाहा और ना किसी ने पूछा। तो तीन महीने पहले अपने ही जीते राज्य में काग्रेस की 2014 से भी बुरी गत क्यों हो गई इसका जवाब कांग्रेसी होने में ही छिपा है जो मान कर चलते है कि वे सत्ता के लिये ही बने है।

आखरी सवाल है, इस जनादेश के बाद होगा क्या? क्योकि देश ना तो विज्ञान को मान रहा है। ना ही विकास को समझ सका। ना ही सच जानना चाहा है। ना ही प्रेम या सोहार्द उसकी रगो में दौड रहा है। वह तो हिन्दु होकर देशभक्त बनकर कुछ ऐसा करने पर आमादा है जहा शिक्षा-स्वास्थय-पानी -पर्यावरण बेमानी से लगे। और देश का प्रधानमंत्री उस राजा की तरह नजर आये जिसे जनता की फिक्र इतनी है कि वह दुश्मन के घर में घुस कर वार करने की ताकत रखता हो। और राजा किसी देवता सरीखा नजर आये। जंहा संविधान, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग भी बेमानी हो जाये। क्योंकि तीन महीने पहले ''इस बार 300 पार '' का ऐलान करते हुये तीन महीने बाद तीन सौ पर कर देना किसी पीएम के लिये चाहे मुश्किल हो लेकिन किसी राजा या देवता के लिये कतई मुश्किल नही है।

आखिर चूक कहां पर हो गई?

– सचिन कुमार खुदशाह –

हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को मैं पार्टी की जीत के रूप में देखता हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुमनाम सांसद जीत कर आए हैं जो पहली बार संसद में कदम रखने वाले हैं। इसीलिए मैं इसे भाजपा की टीम वर्क का नतीजा और उनकी स्ट्रेटजी को निर्णायक मानता हूं। इसके बहुत सारे पहलू हैं इन पर बात अलग से की जा सकती है। फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि चूक कहां पर हो गई। और उसके विश्लेषण पर बात बार – बार होती रहनी चाहिए और हां जिस प्रकार से मोदी ने जीत के तुरंत बाद कहा कि अब हम 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। क्या ठीक इसी प्रकार विपक्षी पार्टियां अपने आप को 2024 की तैयारी में लगाएगी या फिर अफीम की नींद में सो जाएगी पहले की तरह?

2019 आम चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इसे आप विपक्ष के नजरिये बरअक्स दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दें और चुप बैठ जाएं। दूसरा तरीका है कि आप विश्लेषण करें पीछे जाएं और अपनी की हुई गलतियों को चिन्हित करें और उस पर बात करें। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो भला यही होगा कि आप ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ दे।

यह बातें इतनी आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं। भारत का एक पढ़ा – लिखा चेतन मस्तिष्क वाला वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग कहें या एक प्रगतिशील वर्ग या ऐसा वर्ग जो कट्टरपंथी नहीं है। वह वर्ग भारतीय जनता पार्टी के इस जीत को अपने हार के रूप में देखता है और देख भी रहा है। पुरस्कार वापसी से लेकर अब तक देखें तो एक जो समतावादी वर्ग है जो लोकतांत्रिक ढंग से देश को चलते हुए देखना चाहता है। जिसमें समता समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो। वह कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन बात सिर्फ उसके ठगे जाने की नहीं है, अब तो बात करने की जरूरत है कि चूक कहां पर हो गई। आइए, हम इसके अलग – अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के तमाम नीतियों की ओर यदि जाएं जो पिछले 5 सालों में दिखाई पड़ती है। तो चाहे मामला नोटबंदी का हो या जीएसटी का हो या फिर मॉब लिचिंग का या फिर उन नीतियों का जिन्होंने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। राफेल से लेकर पुलवामा की घटना, करकरे से लेकर एक शहीद को बेइज्जत करने की घटना को यदि आप याद करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आखिर इन सबके होने के बावजूद मोदी और उनकी सरकार या कहें उनकी पार्टी इतने बड़े बहुमत से कैसे जीत गई? क्या लोगों में चेतना की कमी है या फिर लोग गंभीरता से इन मुद्दों को नहीं ले पा रहे हैं?

चुनाव विश्लेषक यह मानकर चल रहे हैं या जो डाटा सामने आ रहा है वह यह बताता है की 18 से 27 साल के वोटर्स बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसके हैं। यानी युवा वोटर्स पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन वहीं यदि दूसरी ओर कहें तो विपक्षी पार्टियां चाहे वह कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो या फिर वामपंथी पार्टियां या कहे समाजवादी पार्टियां। इन लोगों ने मुद्दों को उस ढंग से नहीं लिया जिस ढंग से उन्हें लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम नाकामियों को जनता तक ले जाने में नाकामयाब रहे और उन्हें यह समझाने में कहीं ना कहीं फेल साबित हुए की वे भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार और नेता दे सकते थे अब हम बात करते हैं प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की।

कार्बन कॉपी नहीं चलेगा: यदि कांग्रेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस में केवल एक ही व्यक्ति लड़ रहा था। वह है राहुल गांधी। बाकी उनकी टीम और उनके बूथ लेवल कार्यकर्ता नदारद थे। नदारद थे – मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ वोट को अपनी ओर खींचने में मदद नहीं करता बल्कि अपने विचार को भी मतदाताओं तक पहुंचाने का काम करता है। एक टीम भावना जो होनी चाहिए वह कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में नहीं दिखी और कांग्रेस का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि अभी हाल ही में जिन – जिन तीन राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की वह भी स्थानीय नेताओं की गुटबंदी का शिकार हो गया। जो वोट उनको पिछले बार मिले थे उन वोट को भी वह स्थायी नहीं रख पाई और लोकसभा में करारी हार हुई।

राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी एक अपरिपक्व नेता के रूप में वह सामने दिखाई पड़ते हैं। विदेश जाकर कभी वह गंभीरता से आरएसएस की बुराइयों को गिनाते हैं और मॉब लिचिंग की बात करते हैं। जीएसटी की बात करते हैं तो लगता है कि वह बेहद बुद्धिमान है। लेकिन जब वही राहुल गांधी देश में आते हैं तो नरेंद्र मोदी की ही तरह अपने हिदुत्व की छवि को सामने लाने की कोशिश करते हैं और मंदिर मंदिर माथा टेकते हैं। कभी अपने जनेऊ को दिखाते हैं तो लगता है कि वे अपरिपक्व और भाजपा की कार्बन कापी बन रहे हैं। कांग्रेस को उसके यही सॉफ्ट हिदुत्व ने ठिकाने लगा दिया है। मैं इसके पहले के अपने आर्टिकल्स मे इन बातों को ला चुका हूं कि जनता को सॉफ्ट हिदुत्व नहीं चाहिए। जिसे हिदुत्व चाहिए वह कट्टर हिदुत्व ही चाहेगा लेकिन यह बात कांग्रेस के नेताओं तक शायद नहीं पहुंच पाई। राहुल गांधी तक नही पहुंच पाई। वे लगातार सॉफ्ट हिदुओं को लेकर काम कर रहे थे और वह उनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा था। याने देश ने मोदी की कार्बन कापी बनने की कोशिश करते हुए राहुल को सिरे से नकार दिया है।

तो फिर देश को क्या चाहिए? दरअसल भारत एक विविधता वाला देश है इस देश को तमाम विविधताओं के बीच आजादी के साथ रहने की एक आदत है, एक स्वभाव है। उस स्वभाव को जगाना पड़ेगा कट्टर हिंदुत्व के बजाय स्वयं हिंदू समाज ही सबको लेकर चलने वाले विचारधारा को मानता है। लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। प्रगतिशील विचारधारा को लेकर के चलने वाले नेता को वह खोजता है। राहुल में वह नेता नहीं मिलता है। तो मजबूरन उसे कट्टर हिंदुत्व को जाना पड़ता है। और सॉफ्ट हिदुत्व वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ जाता है।

आइए, इस बीच हम वामपंथी और अंबेडकरवादी विचारधाराओं के मानने वालों पर भी बातचीत करें।

हिंदू विचारधारा की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी की जीत पर यदि किसी को सबसे ज्यादा झटका पहुंचा है तो वह यही दो विचारधाराएं हैं। लेकिन यह सोचना पड़ेगा और यह समझने की भी कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर इन दोनों समतावादी विचारधाराओं और उनके व्यक्तियों से आखिर क्या चूक हो गई? की वह सत्ता परिवर्तन करने के अपने प्रयास में नाकामयाब हो गए। मैं इस नाकामयाबी को अपने पुराने प्रश्न की ओर जाने की कोशिश करूंगा। जिसमें ऊपर के पैराग्राफ में लिखा गया है कि यंग वोटर्स पर मोदी ने ध्यान केंद्रित किया। चाहे उन्होंने इन वोटरों को सैनिकों की शहादत पर ध्रुवीकृत किया हो या फिर कट्टर राष्ट्रवाद पर। मोदी अपने आरएसएस के बनाए एजेंडे पर अडिग हैं और वह उसी एजेंडे पर युवाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि यह बात सही है कि इस काम में स्ट्रीम मीडिया ने मोदी की पूरी मदद की है और वैसा मीडिया फिलहाल विपक्ष वामपंथियों या अंबेडकरवादियों के पास नहीं है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं चूक हुई है जिस पर बात होनी चाहिए।

और हां मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि यदि भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो वह इस चुनाव में बिल्कुल मोदी के साथ खड़ा हुआ दिखता है जिस प्रकार से नमो टीवी के माध्यम से चुनाव प्रचार होता रहा और भा जा पा के बड़े नेताओं की गलतियों पर चुनाव आयोग पर्दा डालता रहा या उसे क्षमा करता रहा। यह भी एक पहलू याद रखना वाला है।

अब हम बात करते हैं उन दो विचारधाराओं की जिन्हें इस चुनाव के बाद झटका लगा। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं की इन दो विचारधाराओं को आम जनता तक पहुंचाने में क्या प्रयास किया गया। भारत में सबसे ज्यादा युवा वोटर्स हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करते हैं । उन तक इनकी पहुंच है या नहीं कितने युवा हैं जो इन से जुड़े हुए हैं। या वे युवा तमाम युवाओं को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं या नहीं। यह एक बड़ा प्रश्न है और इसके साथ एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या वामपंथ और अंबेडकर वाद बुढे लोगों की विचारधारा बनकर रह गया है।

यदि वामपंथियों की बात करें तो पूरे देश के वामपंथियों ने कन्हैया पर जिस तरह से ध्यान केंद्रित किया और उन्हें तन मन धन से सपोर्ट किया यदि यही काम वे अपने – अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में किए होते तो शायद कुछ रिजल्ट बेहतर होता हालांकि कन्हैया कुमार भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या यह दोनों विचारधाराएं अपने आंदोलन को व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित किए हुए हैं या सोशल मीडिया से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इनके प्रयास इस लोकसभा में वोट के रूप में परिणित होते नहीं दिखते हैं। वे लोग जो तीन राज्य में हुए कांग्रेस की जीत का क्रेडिट लेते रहे हैं। यह सोचना होगा की किस प्रकार से अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है।

अब यह नहीं चलेगा कि आप मार्क्सवाद को माने साथ में अपने घरों में देवी – देवताओं की तस्वीर भी लगाएं। अब यह नहीं चलने वाला कि आप सिर्फ अंबेडकर की फोटो दिखाकर वोट मांग ले और कोई आप को वोट देता चला जाए। मैं पहले भी कहता आया हूं कि वोटर्स को बेवकूफ या बुद्धिहीन समझने की भूल कभी ना करें। नहीं तो धोखा मिलेगा वामपंथ की गलतियां आज पश्चिम बंगाल में सिर चढ़कर बोल रही है। वहां पर जिस गति से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है इसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि कभी वहां पर वामपंथ की भी विचारधारा रही होगी। हमें चूक को ध्यान देने की जरूरत है ।

इन सबके बीच जो बातें मुझे सबसे ज्यादा विचलित करती है वह है प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों के जीत के क्या मायने हैं? क्या भारत का मतदाता इतना अंधा हो गया है या फिर कुछ और है कारण। जैसे वोटों का पोलराइजेशन। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को मैं पार्टी की जीत देखता हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुमनाम सांसद जीत कर आए हैं जो पहली बार संसद में कदम रखने वाले हैं। इसीलिए मैं इसे भाजपा की टीम वर्क का नतीजा और उनकी स्ट्रेटजी को निर्णायक मानता हूं। इसके बहुत सारे पहलू हैं इन पर बात अलग से की जा सकती है। फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि चूक कहां पर हो गई। और उसके विश्लेषण पर बात बार – बार होती रहनी चाहिए। और हां जिस प्रकार से मोदी ने जीत के तुरंत बाद कहा कि अब हम 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। क्या ठीक इसी प्रकार विपक्षी पार्टियां अपने आप को 2024 की तैयारी में लगाएगी या फिर अफीम की नींद में सो जाएगी पहले की तरह?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

देशबन्धु से साभार

जातिवाद से आजाद होता देश का लोकतंत्र

– डॉ. नीलम महेंद्र –

2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। इस बार के चुनावों की खास बात यह थी कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव परिणामों पर देश ही नहीं दुनिया भर की नज़रें टिकी थी। और इन चुनावों के परिणामों ने विश्व में जो आधुनिक भारत की नई छवि बन रही थी उस पर अपनी ठोस मोहर लगा दी है कि ये वो भारत है जिसका केवल नेतृत्व ही नहीं बदला बल्कि यहां का जनमानस भी बदला है उसकी सोच भी बदल रही है। ये वो भारत है जो केवल बाहर से ही नहीं भीतर से भी बदल रहा है। इस भारत का लोकतंत्र भी बदल रहा है। जो लोकतंत्र जातिवाद मजहब समुदाय की बेड़ियों में कैद था उसे विकास ने आज़ाद करा लिया है। इसकी बानगी दिखी नतीज़ों के बाद जब सेंसेक्स ने भी मोदी सरकार की वापसी पर रिकॉर्ड 40000 की उछाल दर्ज की।

आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी गैर कांग्रेस सरकार को दोबारा जनता ने सत्ता की बागडोर सौंप दी हो वो भी पिछली बार से ज्यादा बहुमत के साथ। और आज़ाद भारत के इतिहास में कांग्रेस के साथ लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वो संसद में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने लायक संख्याबल भी नहीं जुटा पाई हो। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का विषय होना चाहिए कि उसका यह प्रदर्शन तो आपातकाल के बाद हुए चुनावों में भी नहीं था। 1977 के अपने उस सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस ने 152 सीटें जीती थी। दरअसल इन पांच सालों में और खास तौर पर चुनावों के दौरान देश को अगर किसी ने निराश किया है तो कांग्रेस ने। क्योंकि इन पांच सालों में उसने अपने किसी भी काम से ना तो भाजपा को चुनौती दी और ना ही खुद को लोगों के सामने भाजपा अथवा मोदी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। वो अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करने के बजाए भाजपा की खराब परफॉर्मेंस का इंतजार करती रही। शायद कांग्रेस ने राजनैतिक पंडितों के इस गणित पर भरोसा कर लिया था कि भाजपा 2014 में अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी है और उसने हर राज्य में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है कि वो अपने इस प्रदर्शन को किसी भी हालत में दोहरा नहीं सकती। और सत्ताविरोधी लहर के चलते उसकी सीटें हर राज्य में निश्चित ही कम होंगी। इसके अलावा उत्तरप्रदेश में सपा बसपा का गठजोड़ उसे 15 – 20 सीटों तक समेट देगा। यह वाकई निराशाजनक है कि भाजपा की हार में से ही कांग्रेस अपनी जीत के रास्ते खोजती रही। लेकिन वो भूल गई कि शॉर्टकटस से लंबे रास्ते तय नही होते और ना ही किसी की असफलता किसी की सफलता की वजह बन सकती है। सफलता तो नेक नियत और कठोर परिश्रम से हासिल होती है। इसलिए देश की जनता खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम है कि उसने वोट बैंक की राजनीति करने वाले सभी राजनैतिक दलों को एक सकारात्मक संदेश दे दिया है। उत्तरप्रदेश की जनता वाकई बधाई की पात्र है कि जिस राज्य में राजनैतिक दल दलितों यादवों मुसलमानों आदि के वोट प्रतिशत के हिसाब से अपना अपना वोट शेयर आंक कर अपनी सीटों का गणित लगाते थे उस प्रदेश में विकास और अपने काम के बल पर अकेले भाजपा को 50% और कहीं कहीं तो 60% तक का वोट शेयर मिला। जबकि वोट बैंक की राजनीति करने वाले बुआ बबुआ का गठबंधन जो भाजपा को 20 सीटों के अंदर समेट रहा था वो खुद 15 पर सिमट गया। यह पहली बार हुआ कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले हर दल को पूरे देश ने एक ही जवाब दिया। जो कांग्रेस एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही थी उसे असम की जनता ने जवाब दे दिया। जो महबूबा मुफ्ती 370 हटाने पर कश्मीर में भारत के झंडे का अपमान करने की बात करती थी उन्हें जम्मूकश्मीर की जनता ने जवाब दे दिया। जो ममता प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने से ही इंकार कर रही थी और उन्हें जेल में डालने की बात करती थी उन्हें बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया है। नोटबन्दी और जीएसटी पर सरकार को लगातार घेरने वाले विपक्ष को देश ने जवाब दिया। विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जीएसटी लागू करने वाली किसी सरकार की सत्ता में वापसी हुई हो। इसलिए भाजपा की इस अभूतपूर्व विजय में मध्यम वर्ग का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि देश के इतिहास में इतना मतदान पहली बार हुआ है। और आंकड़े बताते है कि जब जब मध्यम वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। दरअसल जो मध्यम वर्ग पहले वोटिंग के प्रति उदासीन रहता था उसने भी इस बार मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो राजनैतिक पंडित उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं के कारण केवल दलितों शोषितों वंचितों का जात और मजहब से ऊपर उठकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने को ही भाजपा की जीत का एकमात्र कारण मान रहे हैं वो या तो नादानी वश कर रहे हैं या फिर स्वार्थवश ऐसा कह रहे हैं।

लेकिन इस सब से परे इन नतीजों ने बहुत से पुराने मिथक तोड़े हैं तो कई नई उम्मीदें भी जगाई हैं। ये वो नतीजे हैं जिन्होंने चुनावों की परिभाषा ही बदल दी। इन नतीजों ने बता दिया कि चुनाव सीटों के अंकगणित का खेल नहीं बल्कि मतदाता का अपने नेता के ऊपर विश्वास के रसायन से उपजे समीकरण हैं। इसलिए चुनावो में गणित की तर्ज पर दो और दो मिल चार कभी नहीं होते बल्कि दो और दो मिलकर बाईस होंगे या बैक फायर होकर शून्य बन जाएंगे यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे जिस पिछले चुनावों में विपक्ष के लिए मोदी को चाय वाला और नीच कहना भारी पड़ गया तो इस बार चौकीदार चोर है के नारे लगवाना। झूठे नैरेटिव बना कर जो चोर न हो उसे चोर कहना जो भ्रष्ट ना हो उसे भ्रष्ट कहना जो ईमानदार है उसे बेईमान कहना विपक्ष को किस कदर भारी पड़ने वाला है इसका अंदाज़ा शायद उन्हें भी नहीं था।

दरसअल स्वार्थ वंशवाद अवसरवाद की राजनीति को जनता अब समझने लगी है। इन चुनाव परिणामों से जनता ने जवाब दे दिया है कि जो काम करेगा वो ही राज करेगा। लेकिन विपक्ष की परेशानी यह है कि मोदी ने एक बहुत बड़ी रेखा खींच ली है और अफसोस की बात यह है कि उस रेखा की बराबरी करने की ताकत विपक्ष में हो ना हो लेकिन जज्बा नहीं है। शायद इसलिए वो लगातार मोदी की बनाई लकीर को छोटी करने में लगा है।

लोकसभा चुनाव जीतकर आये 233 नेताओं पर आपराधिक मामले

शिमला/शैल। राजनीति को अपराध मुक्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी 17वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर आये नेताओं में से 233 (43 प्रतिशत) के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। नामांकन पत्र भरते समय दिये गये हलफनामों से यह बात सामने आयी है कि विजयी उम्मीदवारों में से 159 (29 प्रतिशत) के विरुद्ध संगीन किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि शामिल हैं। नेशनल इलेक्शन वाच के आकलन के अनुसार अपने हल्फनामों में 10 निर्वाचित सांसदों ने तो आपराधिक मामलों में सजा होने की बात तक स्वीकार की है। इनमें से पांच भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गये हैं जबकि चार कांग्रेस और एक वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं। इलेक्शन वाच ने इस बार कुल 539 निर्वाचित सांसदों की उनकी घोषाणाओं को लेकर विश्लेषण किया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 185 विजयी सांसदों (34 प्रतिशत) के विरुद्ध तथा 2009 के चुनाव में 162 विजयी सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे।

लोकसभा क्षेत्र	कुल सीट	दल का नाम	विजयी
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
2. आंध्र प्रदेश	25	तेलुगु देशम	3
		युवजन श्रमिक रयाथु कांग्रेस पार्टी	22
3. अरुणाचल प्रदेश	2	भारतीय जनता पार्टी	2
4. असम	14	ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	1
		भारतीय जनता पार्टी	9
		निर्दलीय	
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	3
5. बिहार	40	भारतीय जनता पार्टी	17
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
		जनता दल (यूनाइटेड)	16
		लोक जन शक्ति पार्टी	6
6. चंडीगढ़	1	भारतीय जनता पार्टी	1
7. छत्तीसगढ़	11	भारतीय जनता पार्टी	9
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	2
8. दादरा एवं नागर हवेली	1	निर्दलीय	1
9. दमन और दीव	1	भारतीय जनता पार्टी	1
10. गोवा	2	भारतीय जनता पार्टी	1
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
11. गुजरात	26	भारतीय जनता पार्टी	26
12. हरियाणा	10	भारतीय जनता पार्टी	10
13. हिमाचल प्रदेश	4	भारतीय जनता पार्टी	4
14. जम्मू -कश्मीर	6	भारतीय जनता पार्टी	3
		जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल कॉंफ्रेंस	3
15. झारखंड	14	आजसु पार्टी	1
		भारतीय जनता पार्टी	11
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
		झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	1
16. कर्नाटक	28	भारतीय जनता पार्टी	25
		निर्दलीय	1
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
		जनता दल (सेक्युलर)	1
17. केरल	20	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	1
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	15
		इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	2
		केरल कांग्रेस(एम)	1
		रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	1
18. लक्षद्वीप	1	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	1
19. मध्य प्रदेश	29	भारतीय जनता पार्टी	28
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
20. महाराष्ट	48	ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन	1
		भारतीय जनता पार्टी	23
		निर्दलीय	1
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
		नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	4
		शिवसेना	18
21. मणिपुर	2	भारतीय जनता पार्टी	1
		नागालैंड पीपुल्स फ्रंट	1
22. मेघालय	2	इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
		नेशनल पीपुल्स पार्टी	1
23. मिजोरम	1	मिजो नेशनल फ्रंट	1
24. नागालैंड	1	नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी	1
25. दिल्ली	7	भारतीय जनता पार्टी	7
26. ओडिशा	21	भारतीय जनता पार्टी	8
		बीजू जनता दल	12
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
27. पुडुचेरी	1	इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
28. पंजाब	13	आम आदमी पार्टी	1
		भारतीय जनता पार्टी	2
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	8
		शिरोमणि अकाली दल	2
29. राजस्थान	25	भारतीय जनता पार्टी	24
		राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	1
30. सिक्किम	1	सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा	1
31. तमिलनाडु	38	ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	1
		कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	2
		कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	2
		द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	23
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	8
		इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	1
		विदुथलाई चिरूथईगल काची	1
32. तेलंगाना	17	ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन	1
		भारतीय जनता पार्टी	4
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	3
		तेलंगाना राष्ट्रीय समिति	9
33. त्रिपुरा	2	भारतीय जनता पार्टी	2
34. उत्तर प्रदेश	80	अपना दल (सोनेलाल)	2
		बहुजन समाज पार्टी	10
		भारतीय जनता पार्टी	62
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	1
		समाजवादी पार्टी	5
35. उत्तराखंड	5	भारतीय जनता पार्टी	5
36. पश्चिम बंगाल	42	आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	22
		भारतीय जनता पार्टी	18
		इंडियन नेशनल कांग्रेस	2

किस दल को कितनी सीटें मिली

दल का नाम	विजयी
आम आदमी पार्टी	1
आजसु पार्टी	1
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	1
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	2
आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	22
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	1
बहुजन समाज पार्टी	10
भारतीय जनता पार्टी	303
बीजू जनता दल	12
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	2
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	3
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	23
इंडियन नेशनल कांग्रेस	52
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	3
जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल कॉंफ्रेंस	3
जनता दल (सेक्युलर)	1
जनता दल (यूनाइटेड)	16
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	1
केरल कांग्रेस (एम)	1
लोक जन शद्रि पार्टी	6
मिजो नेशनल फ्रंट	1
नागालैंड पीपुल्स फ्रंट	1
नेशनल पीपुल्स पार्टी	1
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	5
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी	1
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	1
समाजवादी पार्टी	5
शिरोमणि अकाली दल	2
शिवसेना	18
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा	1
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति	9
तेलुगु देशम	3
युवजन श्रमिक रयाथु कांग्रेस पार्टी	22
अन्य	8
कुल	**542**

साइबर सैल ने तैयार की2019 में धोखाधड़ी करने वालों के मोबाइल नम्बरों की सूची

शिमला/शैल। दुनियाभर में इन्टरनेट और सोशल मीडिया के बड़ते प्रभाव के बीच डाटा चोरी एक गंभीर समस्या बनकर उभरकर सामने आई है। प्राय: यह देखने में आया है की हम डाटा की बढ़ती उपयोगिता और उसकी सुरक्षा को लेकर विकसित देशो की अपेक्षा कम जागरूक व संजीदा है। यहाँ पर कई कंपनिया अपने ग्राहकों का बड़ी संख्या में डाटा इकटठा कर रही है जिसके दुरूपयोग होने से ग्राहकों को भारी आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।

हिमाचल प्रदेश साइबर थाना शिमला में प्राप्त हुई शिकायतों के विश्लेषण करने पर पाया गया है कि वर्तमान समय में धोखेबाज़ फेसबुक पर अपने टारगेट को चूज़ करते हैं। फेक प्रोफाइल बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जिस देश का फ्रेंड होता है उसी कंट्री का वर्चुअल नंबर लेते हैं। जैसे अमेरिका के किसी शख्स को चूना लगाने के लिए अमेरिका का वर्चुअल नंबर लेते हैं। शिकार ब्रिटेन से है, तो ब्रिटेन का वर्चुअल नंबर लेते हैं। वर्चुअल नंबर एक ऐसी सर्विस है, जिसे कोई भी आदमी खरीद सकता है। मोबाइल फोन पर वॉटसऐप को उस विदेशी नंबर से इनेबल कर सकता है। ऐसे में जब भी वह पीड़ित से बात करता है, तब पीड़ित को लगता है की यह कॉल अमेरिका से या ब्रिटेन से आ रही है, वो इसलिए गुमराह हो जाते हैं। ये प्रोफाइल पर बड़ा ही हैंडसम और अमीर लोगों का फोटो लगाते हैं। आदमी को लगता है कि वह किसी ब्रिटिश से बात कर रहा है। जबकि विदेशों के कुछ धोखेबाज़ लड़कों ने ठगी का ये जाल बनाया हुआ है और ये ठग इंडिया से ही कॉल कर रहे होते हैं वैवाहिक साइटस व फ्रेंडशिप चैट के लिए कोई भी पुरुष व महिला बनकर अकसर लोगों से बात करता/करती हैं। तो आम जनता से अनुरोध है की उपरोक्त वर्चुअल नंबर्स से कॉल आने पर इनके झांसे में ना आये तथा तुरंत राज्य साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला से संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश गुप्तचर विभाग के राज्य साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला द्वारा वर्ष 2019 में इस समय तक फाइनेंसियल फ्रॉड की 276 शिकायत व सोशल मीडिया से सम्बंधित । शिकायत प्राप्त हो चुकी है। इन शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए साइबर थाना शिमला द्वारा करीब 04 लाख से अधिक राशी पीड़ित शिकायतकर्ता को धोखेबाज़ों के अकाउंट से रिफंड करवाया जा चुका है। राज्य साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला द्वारा वर्ष 2019 में धोखाधड़ी करने वालों के सभी मोबाइल नम्बरों की सुची तैयार की है जिसके द्वारा आम जनता को ठगने का प्रयास किया गया है। इन मोबाइल नम्बरों की संख्या करीब 382 है। यह सभी नम्बर बाहरी राज्यों के टलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं। इन संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की सूची को गुप्तचर विभाग हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर-प्रदेश, झारखंड, नई दिल्ली व अंडमान निकोबार को इनके विरूध उचित कार्यवाही करने के लिये भेजा गया है। क्योंकि ये मोबाइल नम्बर उपरोक्त राज्यों के टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की सूची टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स के नोडल आफिसर को इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये दे दी गई है। राज्य का साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला साइबर अपराध पर निरंतर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। आम जन मानस को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरुक किया जा रहा है कि वे संदिग्ध काल, ई-मेल द्वारा मांगी जा रही बैंक खाते की डिटेल प्रदान न करे अन्य किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं एवं इस प्रकार के फिलशग अटैक से सतर्क रहें क्यूंकि साइबर क्राइम से बचने का एकमात्र सटीक उपाय साइबर अपराध के सन्दर्भ में जागरूकता ही है। किसी भी संदिग्ध के संदर्भ में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के टेलीफोन न. 0177-2620331, 2621331 व ई-मेल cybercrcell-hp@nic.in पर तुरंत संपर्क करें।

पीएसएलवी-सी46 ने रिसैट-2बी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया

शिमला/शैल। भारत के पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी-सी46) ने आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) एसएचएआर से रिसैट-2बी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर का यह 72वां लॉन्च व्हीकल मिशन था और फर्स्ट लॉन्च पैड से यह 36वां प्रक्षेपण था।

पीएसएलवी-सी46 ने फर्स्ट लॉन्च पैड से 05:30 बजे (आईएसटी) उड़ान भरी और उड़ान भरने के 15 मिनट 25 सेकंड के बाद रीसैट-2बी को 556 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया। अलग होने के बाद रीसैट-2बी के सौर उपकरण स्वत: तैनात हो गए और बेंगलुरू स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रेकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) ने रीसैट-2बी को नियंत्रण में ले लिया। आने वाले दिनों में सेटेलाइट पूर्ण संचालन की स्थिति प्राप्त कर लेगा।

रीसैट-2बी का वजन 615 किलोग्राम है और यह रडार इमेजिंग पृथ्वी पर्यवेक्षण सेटेलाइट है। यह सेटेलाइट कृषि, वानिकी और आपदा राहत के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगा।

इसरो के चेयरमैन डॉ. के शिवन ने मिशन में कार्यरत लॉन्च व्हीकल और सेटेलाइट टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ ही पीएसएलवी ने 354 सेटेलाइट लॉन्च किए हैं और 50 टन भार को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। इन सेटेलाइटों में राष्ट्रीय और विदेशी सेटेलाइट शामिल हैं।

डॉ. के. शिवन ने मिशन में लगाए गए दो हलके पेलोड-सेमी कंडक्टर लेबोरेट्री (एससीएल), चंडीगढ़ द्वारा विकसित विक्रम प्रोसेसर तथा इसरो इनरटियल सिस्टम यूनिट, तिरूअनंतपुरम द्वारा विकसित किफायती एमईएमएस आधारित इनरटियल नेवीगेशन सिस्टम (आईएनएस) के लिए भी टीमों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि रीसेट-2बी एक आधुनिक पृथ्वी पर्यवेक्षण सेटेलाइट है और इसमें 3.6 मीटर रेडियल रिब एंटिना तकनीक का उपयोग किया गया है। लॉन्च कार्यक्रम को लगभग पांच हजार लोगों ने दर्शक दीर्घा से देखा, जिसे आम लोगों के लिए खुला रखा गया था। इसरो अब चंद्रयान-2 को 9 जुलाई से 16 जुलाई, 2019 के बीच लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आशा है कि चंद्रयान-2 छह सितम्बर 2019 को चांद पर उतरेगा।

बदलते समय के साथ विदेशी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक

शिमला/शैल। शिमला स्कूल ऑफ फॉरन लैंग्वेज ने जर्मन लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट ''इनडैफ ऑन व्हील्स'' के तहत शिमला में 27.05.2019 को भारतीय संस्थान में आधुनिक वेब टूल्स के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से मदर डे टीचिंग और लर्निंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता जर्मन अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मी सिखर केलप्पू ने की और स्कूल ऑफ़ फॉरन लैंग्वेज शिमला की प्राचार्य सीमा शर्मा ने की। सीमा शर्मा बताया कि प्रौद्योगिकी के इस युग में आधुनिक तकनीकों के लाभों को समझाया, इस संगोष्ठी में कई छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। उन्होने

बताया जर्मन भाषा आज तेजी से युवाओं के अपनी पकड़ बना रही है इसका लाभ छात्र जर्मनी में अपने उच्च अध्ययन करने के लिये कर सकते हैं और एक सफल कैरियर बना सकते हैं। स्कूल ऑफ फॉरन लैंग्वेज, शिमला में पिछले 5 वर्षों से छात्रों को जर्मन भाषा पढ़ा रहा है। जिनमें से कई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जर्मनी काम करने जा चुके हैं । इस इंस्टीटयूट से प्रशिक्षित छात्र आज केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन शिक्षकों के तौर काम कर रहे है। कॉरपोरेट क्षेत्र में डॉक्टरों, इंजीनियरों को जो कि व्यापक निवेश और फैलोशिप प्राप्त करने के लिए जर्मनी जाना चाहते है को भी यहां प्रशिक्षित किया जा रहा है। बदलते समय के साथ, अब विदेशी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक हो गया है क्योंकि दुनिया छोटी होती जा रही है और आकांक्षाएं अधिक हो रही हैं।

ब्रहमोस हवाई प्रक्षेपित मिसाइल को एसयू-30 एमकेआई विमान से छोड़ा गया

शिमला/शैल। भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से आज सफलतापूर्वक ब्रहमोस हवाई प्रक्षेपित मिसाइल छोड़ा। विमान से प्रक्षेपण आसानी से हुआ और मिसाइल जमीन पर लक्ष्य को सीधे मारने से पहले वांछित प्रक्षेपपथ पर चला गया।

हवाई प्रक्षेपित 2.5 टन का ब्रहमोस मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। बीएपीएल ने इसका डिजाइन तैयार किया है और इसे विकसित किया है। भारतीय वायुसेना दुनिया की पहली वायुसेना बन गई है, जो इस श्रेणी के जमीन पर हमला करने वाले समुद्र पर लक्षित 2.8 मैक मिसाइल को 22 नवंबर, 2017 को सफलतापूर्वक छोड़ चुकी है। आज इस तरह के हथियार का दूसरी बार प्रक्षेपण किया गया। विमान में इस हथियार को जोड़ना एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि विमान में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व में आने के बाद से इस कार्य में लगी हुई है। विमान के सॉफ्टवेयर को विकसित करने का काम भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने अपने हाथ में लिया, जबकि एचएएल ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रोनिकल सुधार किए। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, बीएपीएल और एचएएल के समर्पित प्रयासों ने ऐसे जटिल कार्यो को हाथ में लेने की देश की क्षमता को साबित कर दिया है।

ब्रहमोस मिसाइल दिन अथवा रात तथा हर मौसम में भारतीय वायुसेना को समुद्र अथवा जमीन पर किसी भी लक्ष्य को सटीक निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करता है।

अपने उद्देश्य पर खरा नहीं उतर पाया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल:विनोद

शिमला/शैल। प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ की प्राासनिक ट्रिब्यूनल को बन्द करने पर आन्दोलन की धमकी को हि.प्र. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हस्यास्पद करार देते हुए कहा है कि सचिवालय कर्मचारी संघ के नेताओं का यह ब्यान प्रदेश भर में अपनी सेवायें देने वाले कर्मचारियों की समस्याओं और उनके मुद्दों पर उनकी ना समझी को दर्शाता है। महासंघ के संयोजक विनोद कुमार ने सचिवालय कर्मी संघ के नेताओं से यह पूछा है कि आप यह सार्वजनिक करें कि आज तक कर्मचारी समस्याओं और सरकार द्वारा राजनीतिक और बदले की भावना से प्रताड़ित कर्मीयों की उन्होंने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय में कितने मामलों पर लड़ाई लडी हैं। सचिवालय कर्मी संघ नेताओं की ऐसी ब्यानवाजी से यह स्वयं स्पष्ट होता है कि प्रदेश के कर्मीयों को समय पर न्याय न मिल सके और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर इनका हमेशा दबदबा बना रहे। महासंघ का सचिवालय कर्मी नेताओं को यह प्रस्वाव है कि क्यों न सचिवालय कर्मचारियों के कैडर को भी ''यूनिफाईड कैडर'' करने की मांग सरकार से की जाये ताकि वह भी प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की पीड़ा और उनकी मूलभूत समस्याओं की जानकारी हासिल कर सके ।

महासंघ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की पुर्नसमीक्षा बारे मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर की पहल का समर्थन करता है और सरकार से मांग की जाती है कि इस पूरे मामले पर खुली बहस हो, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी नेताओं को भी शामिल किया जाये। पूर्व के यह उदाहरण हैं कि जिस उद्देश्य से 1986 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था, वह उस पर खरा नहीं उतर पाया और उसके बाद कर्मचारी संगठनों की तरफ से इसे बन्द करने की मांग उठने लगी तथा पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारी संघों की मांग पर कर्मचारियों के ''सेवायें मामलों'' की पैरवी के लिए ट्रिब्यूनल को बन्द करके उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को जहां कानूनन न्याय मिलना प्रारम्भ हुआ, वहीं कर्मचारियों की राजनीतिक और बदले की भावना से प्रताड़ना पर भी काफी हद तक रोक लग चुकी थी। परन्तु प्रदेश के कुछ राजनेताओं को यह सब रास नहीं आया और फिर राजनीतिक नज़रिये से ट्रिब्यूनल को कांग्रेस सरकार ने पुन: चालू कर दिया और आज भी स्थिति पूर्व की तरह खड़ी हो गई है, चूंकि कर्मचारियों के जो मामले माननीय उच्च न्यायालय से ट्रिब्यूनल को सुनवाई के लिए आयें, वह आज भी यथावत हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

छात्रवृति घोटाले की प्रारम्भिक जांच पर उठे सवाल

♦क्या छात्रवृति घोटाले की जांच कुछ संस्थानों की साख पर प्रश्नचिन्ह लगाने की नीयत से है

♦जांचकर्ता पर उठे सवालों से उभरी आशंका

♦सीबीआई को सभी 266 संस्थानों की जांच करना हो जायेगी बाध्यता

शिमला/शैल। छात्रवृति घोटाले की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई को यह जांच शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी प्रारम्भिक जांच के आधार पर सौंपी गयी है। क्योंकि इसी जांच रिपोर्ट पर विभाग ने छोटा शिमला थाना में एफआईआर दर्ज करवायी थी। लेकिन प्रारम्भिक जांच कर्ता शक्ति भूषण ने जिस छात्र सतीश कुमार की शिकायत के आधार पर यह जांच शुरू की और आगे बढ़ाई उसी छात्र का एक शपथपत्र आया है। इस शपथपत्र में छात्र सतीश कुमार ने जांच अधिकारी शक्तिभूषण के खिलाफ आरोप लगाये हैं। आरोप है कि शक्तिभूषण ने डर और लालच देकर यह शिकायत हालिस की है। इसी शपथपत्र के साथ सिरमौर के साईवाला के एक भानू प्रताप को आरटीआई के तहत मिली सूचना भी सामने आयी है। इस सूचना में विभाग से यह पूछा गया था कि क्या छात्रवृति प्राप्त करने के लिये आधार नम्बर का होना अनिवार्य है? तो अधिसूचना की कापी उपलब्ध करवायी जाये। इस पर विभाग ने जवाब दिया है कि सूचना उपलब्ध नही है। आरटीआई में यह जानकारी भी मांगी गयी थी कि क्या छात्रवृति लेने के लिये मोबाईल नम्बर होना आश्वयक है। इसके जवाब में भी विभाग ने सूचना उपलब्ध नही है का ही जवाब दिया है। आरटीआई में यह सूचना 5 अक्तूबर 2018 को आयी है। विभाग के जवाब से साफ हो जाता है कि या तो आधार और मोबाईल नम्बर होने अनिवार्य नही हैं या फिर विभाग को ही छात्रवृति योजना के नियमों की पूरी जानकारी नही है। ऐसे में जांचकर्ता द्वारा इसमें घोटाला होने का आरोप तब तक लगा पाना संभव नही हो सकता जब तक कि कुछ संवद्ध संस्थानों से इस बारे में जानकारी हालिस न कर ली जाती। इस संबंध में कुछ संस्थानों द्वारा विभाग को दिया गया एक ज्ञापन भी सामने आया है। इस ज्ञापन में यह शिकायत की गयी है कि इस कथित घोटाले के बारे में जांचकर्ता ने एक बार भी उनसे जानकारी हालिस करने का प्रयास नही किया है।

HIMACHAL PRADESH

A 240103

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

AFFIDAVIT/ STATEMENT

That I Satish Kumar, aged 23 years, son/daughter of Jagdish Chand, resident of Vill- Hara, Po- Kuthandal, Tehsil Nurpur, District Kangra, HP having Aadhar Card No. 469393425078 is giving this affidavit with my free will & consent and without there being any undue pressure and coercion do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That the deponent in order to pursue his Higher Education had applied for scholarship after fulfilling required documentation for scholarship from the Department of Higher Education (Himachal Pradesh) through proper channel, with his own consent and without any pressure.
2. That deponent has fulfilled all the requisite formalities and documentation for opening of bank account which is mentioned in scholarship application form of Department of Higher Education (Himachal Pradesh) and still operating the said account. In furtherance, Deponent affirms that he has availed the scholarship without any hindrance and got the benefit of the Government schemes to build his carrier.

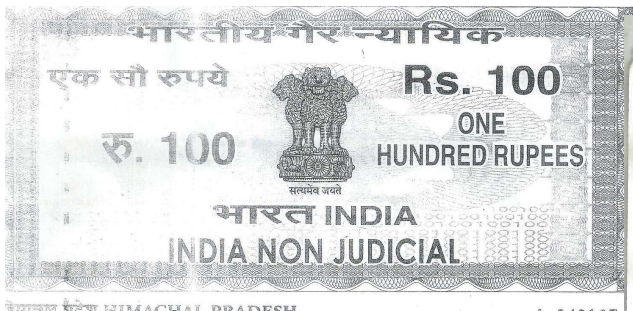

Page 1 of 3

3. That deponent confirms that Mr. Shakti Bhusan has illegally allured him and on account of giving the benefits of "SABAL BHARAT" Schemes got jotted down a complaint from deponent so as to settle his personal scores as well as others purposes etc.
4. That Mr. Shakti Bhusan allured the deponent for giving the scholarship of 15,000/- Per month in Sabal Bharat Scheme and it is the reason that deponent fell in his false Pray and given him the written complaint as per his desire.
5. That Deponent had given the complaint in Police Station, Rehan, tehsil Nurpur, District Kangra, HP and Education Department as well, but after knowing the reality and clarifying the mis-understanding, the deponent got withdrew his complaints with his written letter. It is worthwhile to mention here that through Written letter dated 02.10.2015 and telephonically also he intimated to Mr. Shakti Bhusan to not to take any action on his complaints but Mr. Shakti Bhusan misbehaved with him and without his consent, have been taking the action on his complaints so as to create the hype into the matter and also used the news papers as a tool to widely circulate the same so as to settle his personal score with someone. Written Letter withdrawing the complaint is attached as **A-1.**
6. That deponent further declares that he got the Scholarship Fee from the Higher Education Department (HP) with delay of more than a year. That deponent submits that due to some personal circumstance he couldn't attend the Exams but it is further clarified the he has not cancelled his admission with the institute. That deponent further undertakes that with his consent deponent has transferred

Page 2 of 3

the scholarship into the account of institute through his bank transfer letter.

7. That it is apposite to mention here that now the deponent has come to know that without his consent the name of the deponent is being used in false & frivolous complaints by some people for their personal gains/benefits. Deponent is giving this affidavit to stop/avert all such complaints and further declare that if there is any such previous false complaints concern with his scholarship & admission, Bank accounts in Haryana etc exists so same may kindly be treated closed ab-initio.
8. That now it has come in deponent's knowledge that deponent is being made scapegoat by naming him in some false FIR etc whereas deponent has not registered any FIR and moreover, Nothing wrong has ever happened with the deponent, as deponent has availed the scholarship without any obstacle and with his consent opened the account in Panchkula, Haryana.

Place:
Dated:

Satish Kumar
Deponent

Verification

Verified that the contents of my above said affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Place:
Dated:

Satish Kumar
Deponent

witness:-

Identified by
Sh. Arun Kaundal
Adv. Nurpur.

Page 3 of 3

छात्रवृति योजना से 238089 छात्र लाभार्थी कहे जा रहे हैं। यह छात्र सभी 2772 संस्थानों से हैं। इनमें 2506 सरकारी और 266 प्राईवेट संस्थान हैं। 2506 सरकारी संस्थानों को 2013-14 से 2016-17 56,34,35168 और 266 प्राईवेट संस्थानों को 210,04,33703 रूपये छात्रवृति के आंवटित किये गये हैं। इस आंवटन से यह आभास करवाया जा रहा है कि छात्रवृति की 80% राशि प्राईवेट संस्थानों को ही आवंटित कर दी गयी और इसके पीछे घोटाले की मंशा रही है। इस पर प्राईवेट संस्थानों ने सरकार को सौंपे ज्ञापन में यह खुलासा किया है कि सरकारी संस्थानों में छात्रों से 3000 से 6000 तक फीस ली जाती है जबकि प्राईवेट संस्थानों द्वारा यही फीस 50,000 से 90,000 तक ली जाती है। स्वभाविक है कि जब सरकारी और प्राईवेट संस्थानों में फीस का इतना अन्तर है तो निश्चित रूप से फीस के अनुपात में प्राईवेट संस्थानों के लिये यह आवंटन ज्यादा रहेगा ही।

Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh
"SCHOLARSHIP BRANCH"

Subject: - *Information under Right to Information Act, 2005 in r/o Sh. Bhanu Pratap Singh ,houce No 415, VPO saimwala Tehsil & District Sirmour HP.*

Sir,

Please refer to your UO No. EDN-HE (16) B (15) RTI-01/2018-162 dated 05/09/2018-402 on the subject cited above.

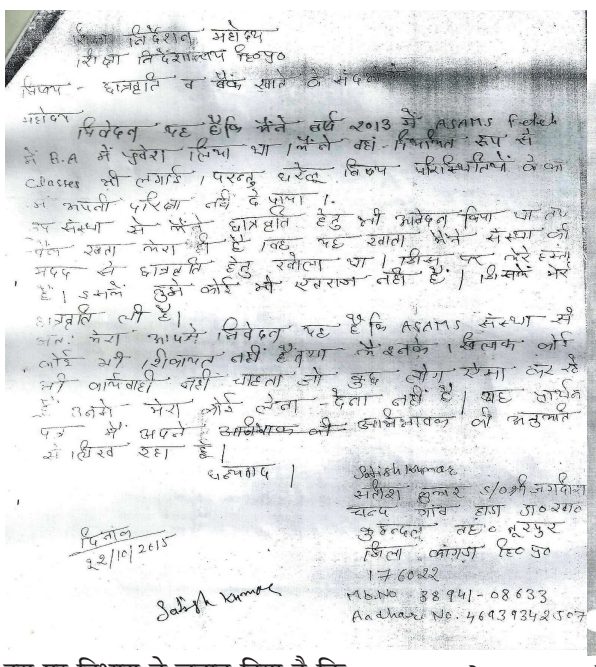

The point wise requisite information is as under:-

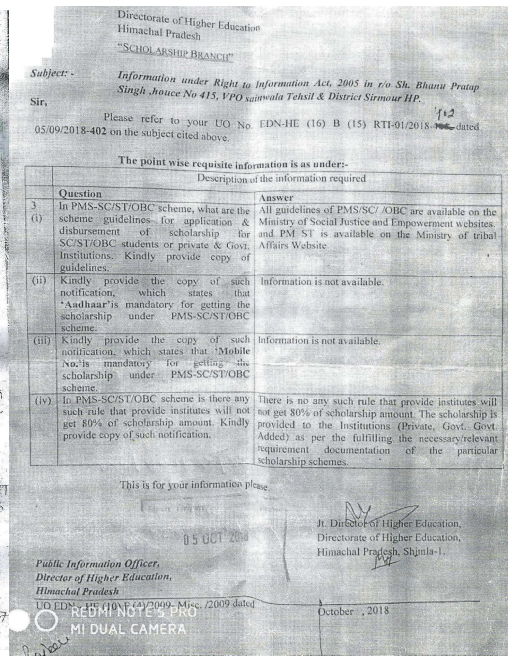

	Description of the information required	
	Question	Answer
3 (i)	In PMS-SC/ST/OBC scheme, what are the scheme guidelines for application & disbursement of scholarship for SC/ST/OBC students or private & Govt. Institutions. Kindly provide copy of guidelines.	All guidelines of PMS/SC/ /OBC are available on the Ministry of Social Justice and Empowerment websites. and PM ST is available on the Ministry of tribal Affairs Website.
(ii)	Kindly provide the copy of such notification, which states that 'Aadhaar'is mandatory for getting the scholarship under PMS-SC/ST/OBC scheme.	Information is not available.
(iii)	Kindly provide the copy of such notification, which states that 'Mobile No.'is mandatory for getting the scholarship under PMS-SC/ST/OBC scheme.	Information is not available.
(iv)	In PMS-SC/ST/OBC scheme is there any such rule that provide institutes will not get 80% of scholarship amount. Kindly provide copy of such notification.	There is no any such rule that provide institutes will not get 80% of scholarship amount. The scholarship is provided to the Institutions (Private, Govt. Govt. Added) as per the fulfilling the necessary/relevant requirement documentation of the particular scholarship schemes.

This is for your information please.

05 OCT 2018

Jt. Director of Higher Education,
Directorate of Higher Education,
Himachal Pradesh, Shimla-1.

Public Information Officer,
Director of Higher Education,
Himachal Pradesh

UO EDN- HE (10) F (4)/2009- Misc. /2009 dated October , 2018

इस कथित घोटाले में यह सामने है कि इस छात्रवृति योजना के तहत सभी सरकारी और प्राईवेट संस्थानों को इस छात्रवृति का आवंटन हुआ है। जांच रिपोर्ट में यह आरोप नही है कि जिन दो दर्जन प्राईवेट संस्थानों की जांच की जा रही उन्हे इसके आवंटन के लिये कोई अपने ही अलग नियम बना लिये थे यदि सभी संस्थानों में एक जैसे ही नियमों और प्रक्रिया से छात्रवृति का आंवटन हुआ है तो फिर सभी संस्थानों की जांच क्यों नही। इस बहुचर्चित घोटाले में यह आरोप है कि कई कई छात्रों के लिये एक ही आधार और मोबाईल नम्बर का प्रयोग किया गया है। जब आरटीआई में दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि आधार नम्बर और मोबाईल नम्बर अनिवार्य होने की कोई अधिसूचना ही नही है तब यह घोटाला होने का आधार कैसे बन गया? इसमें घोटाला तो तब बनेगा जब रिकार्ड पर दिखाया गया लाभार्थी यह कहे कि उसे छात्रवृति मिली ही नही है या फिर रिकार्ड पर दिखाया गया लाभार्थी फर्जी निकले। लेकिन ऐसा कोई आरोप जांच रिपोर्ट में नही लगाया गया है। ऐसे में यह सवाल और शंकाएं उठना स्वभाविक है कि क्या इन दो दर्जन संस्थानों को किसी तय योजना के तहत बदनाम करवाया जा रहा है। क्योंकि जिस भी प्राईवेट संस्थान पर किसी तरह के घपले का आरोप लगेगा वहां नये छात्रों द्वारा दाखिला लेने पर कई प्रश्न उठेंगे और संस्थान की साख प्रभावित होगी।

इस जीत के साथ ही बढ़ी.....पृष्ठ 1 का शेष

प्रत्याशी का कद उस समय बौना हो गया था जब वीरभद्र सिंह ने यह कहा था कि कोई भी मकरझण्डू चुनाव लड़ लेगा। इस ब्यान के बाद कांगड़ा और हमीरपुर से अपने ही तौर पर प्रत्याशीयों के नाम उछाल दिये और अन्त तक उनकी वकालत करते रहे। जब यह प्रत्याशी उनकी पंसद के नही हो पाये तो उन्होने प्रचार के दौरान हर जनसभा में परोक्ष/अपरोक्ष में यह संदेश और संकेत अवश्य दिया कि प्रत्याशी उनकी पसंन्द का नही है। इसी के साथ चुनाव प्रचार में वीरभद्र मुख्यन्त्री जयराम को ईमानदारी का प्रमाणपत्र भी बराबर बांटते रहे। वीरभद्र के इन ब्यानों पर प्रदेश में कोई भी नेता सवाल तक खड़ा नही कर पाया। प्रदेश की प्रभारी रजनी पाटिल लगातार इसी डर में रही कि कौन सा नेता न जाने मंच से कब क्या ब्यान दे दे। कुलदीप राठौर का कद भी अध्यक्ष होने के वाबजूद इतना बड़ा नही हो पाया था कि वह किसी भी बड़े नेता को रोक पाते। इस सबका परिणाम था कि अधिकांश बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता थे ही नही। यहां तक की जब पांवटा साहिब में वीवीपैट और ईवीएम मैच नही कर पायी तो कांग्रेस उसको भी मुद्दा बनाकर उठा नही पायी। इससे यही प्रमाणित होता है कि पार्टी के बड़े नेताओं का एक बड़ा वर्ग अपरोक्ष में भाजपा की मदद कर रहा था। इसको लेकर पार्टी के भीतर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। वीरभद्र ब्रिगेड से लेकर अब तक पूर्व मुख्यमन्त्री की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं।